समाचार एवं विचार सेवा वार्षिक सहयोग राशि 25/–

महाकौशल–संदेश

वर्षः– 18 पृष्ठः– 4 अंक :– **41** संपादक :– डॉ. किशन कछवाहा

RNI No. MPHIN/2001/11140

यह सामग्री 'प्रकाशनार्थ' प्रेषित है। कृपया अपने लोकप्रिय पत्र–पत्रिका में प्रकाशित कर Complimentaryकापी प्रेषित करने की अनुकम्पा करें।

जातिवादी राजनीति मीडिया, कॉग्रेस और दलित

डॉ. किशन कछवाहा

कॉग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा प्रारंभ से ही हिन्दुत्व विरोधी और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति प्रदर्शक रहा है। इस 132 वर्ष पुरानी संस्था ने हर समय साम्प्रदायिक चालें चली और उसके लिये सेक्यूलरिज्म का सहारा लिया और उससे उत्पन्न फूट का लाभ उठाया। आज जिस साफ्ट हिन्दुत्व का चोला ओढ़ा जा रहा है, कभी उसे' भगवा आतंकी कहते हुये तिरस्कृत किया गया था, न केवल दुष्प्रचारित किया वरन् उसे सिद्ध करने निन्दनीय षड़यंत्र भी रचे गये। नये हिन्दूत्व के चोले का लाभ कॉग्रेस को कितना होगा, यह कहना कठिन है क्यों मणिशंकर, कपिल सिब्बल जैसे आत्मघाती नेता एक दो की संख्या में नही हैं। वे सेकुलेरिटी, कम्युनिज्म मार्क्सवाद और प्रगतिशीलता के नाम पर हिन्दूधर्म के प्रति दुर्भावना फैलाने का काम प्रारंभ से ही करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे क्या राहुल उन्हें रोक पायेंगे ? ऐसे निहित स्वार्थी तत्व विभिन्न संस्थाओं राजनैतिक, सांस्कृतिक और पांथिक क्षेत्रों में काम तो करते हैं हिन्दूधर्म के नाम पर लेकिन लामबंद होते हैं हिन्दू धर्म के खिलाफ। मुस्लिम और ईसाईयों द्वारा किया जा रहा 'कनवर्जन' का काम भी लम्बे समय के चल रहा है। इन्हें भी कॉग्रेसियों का ही संरक्षण मिलता रहा है। हिन्दूत्व की तरफ आना कॉग्रेस की एक बड़ी मजबूरी है क्योंकि सोनियाजी के खासमखास कुछ बजनदार चेहरे डॉ. मनमोहन सिंह, अहमद पटेल, गुलामनबी आजाद (और स्वयं सोनिया जी) अल्पसंख्यक समुदाय के थे। इस कारण कॉग्रेस की छवि अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देने वाली बनी हुयी थी और इस छबि के सहारे चुनाव की वैतरणी पार नही की जा सकती। दूसरी ओर कभी देशभर में एक छत्र राज्य करने वाली कॉग्रेस के पास पंजाब और कर्नाटक सहित चार राज्य ही उसकी झोली में रह गये हैं। एक – एक कर राज्यों का सफाया होता जा रहा है। यह गहन चिन्तन का विषय भी है कि इस समय यह पार्टी संकटों से चारों तरफ से घिरी है। कॉग्रेस को गुजरात चुनाव जीतने के लिये जातिवादी राजनीति में हिलोंरे ले रहे तीन युवकों हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश का सहयोग प्राप्त करने की ऐतिहासिक भूल से भले ही क्षणिक लाभ प्राप्त हो सका हो लेकिन जीवन भर की कमाई पर यह दाग तो लग ही गया कि कॉग्रेस जातिवादी राजनीति के मामले में भी पीछे हीं है। सफाई में कुछ भी दलीलें दी जाती रहें लेकिन इससे तो कॉग्रेस की विश्वसनीयता ही दॉव पर लग गयी। जातिगत आरक्षण, साम्प्रदायिकता देश द्रोह जैसे जहर घोलने के आरोप भी लगे। इस सब के बावजूद जी.एस.टी नोट बंदी जैसे मुद्दों का भी विरोध कारगर साबित नही हो सका। विकास को पागल बताना भी गुजरात की जनता को रास नही आया। आखिरकार 22 साल से सत्ता पर आसीन गुजरात की भाजपा को पॉच साल और मिल गये। इससे यही संदेश गया कि नरेन्द्र मोदी की विकासवादी और राष्ट्रवादी नीति विशेष उपलब्धि देने वाली है।

जातिवादी राजनीति देश को कहॉ ले जायेगी ? इसकी सुध किसे है ? वोटों की लालच में कॉग्रेस, कॉग्रेस समर्थित मीडिया का एक वर्ग साथ ही तथा कथित सेकुलर जमात उसमें उलझ गयी है। महाराष्ट्र में तो दलित – मराठा विवाद ने कॉग्रेस की उस हताशा की झलक को भी दिखा ही दिया। दूसरी तरफ गत नवम्बर में 24–25–26 को प्रयासों से संतों और धर्माचार्यों का एक बड़ा सम्मेलन सम्पन्न हुआ जिससे संतों और धर्माचार्यों ने अश्पृश्यता को जड़–मूल से खत्म कर देने का संकल्प लिया है। राजनैतिक दल तो वोट की लोभ – लालच में कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आश्चर्य तब होता है जब मीडिया का एक वर्ग हिन्दुओं को जातियों में बॉटने के कार्य में जुटा दिखाई देता है। उसमें भी तकलीफ तब महसूस होती है जब ऐसे दुष्कृत्य सोची समझी रणनीति के तहत किये जाते हैं। गुजरात के तीन जातीय नेताओं को मीडिया ऐसा उभार देता है, मानो वे जातिवादी जहर सींचते हुये देश का उद्धार करने में लगे हों। मीडिया का ऐसा ही रूप उस समय भी नजर आया था जब जे.एन.यू में '' भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार' जैसे देशद्रोही नारे लगाये जा रहे थे। ऐसे तत्व आज भी मीडिया के तथा कथित उस वर्ग के ऑख के तारे बने हुये हैं। दादरी और अखलाक पर छाती पीट पीटकर दहाड़ मारने वाले सेकुलर और उनके कॉग्रेस आका आज क्यों चुप्पी साघ बैठे है – जब मुस्लिम समाज की लड़कियों का शोषण किये जाने के मामले सामने आचुके हैं। अरब देशों के कामुक शेखों के कुकृत्यों पर उनके औंठ क्यों सिले हुये हैं ? पुराने हैदराबाद में मुस्लिम आबादी अधिक है। वहॉ दशकों से निकाह के नाम पर मुस्लिम लड़कियों से देह–व्यापार कराया जा रहा है। इस बर्बर और घृणित कृत्य के खिलाफ आवाज क्यों नही उठायी जाती ?

कश्मीर, केरल में और म्यॉमार में हिन्दुओं के साथ अमानवीय अत्याचार होते रहते हैं तब भी इन तथा कथित सेकुलरों के मुंह से आवाज नही निकलती। कैसी है इनकी सेकुलेरिटी ? रोहिंग्या मुसलमानों को देश में बसाने की मॉग को जाती है, रोहिंग्याओं के प्रति बड़ा दया भाव पैदा होता है लेकिन यही दया भाव कहॉ गायब हो जाता है जब हिन्दूओं के साथ बर्बर अत्याचार होते हैं, और हत्यायें होती है। इन्हें जे.एन.यू के कन्हैया की चिन्ता होती है रोहिंग्याओं की चिन्ता होती है लेकिन कश्मीरी विस्थापित हिन्दुओं की चिन्ता क्यों नही होती ? आज जातीय राजनीति से देश को कितना नुकसान हो रहा है – इसे समझने कोई तैयार नही है। जातियों को सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है, बोट बैंक के लिये। यह कितनी चिन्ता की बात है। जब छोटी से छोटी घटना को लेकर हिंसा की आग में झौंक दिया जाता है। न्यस्त स्वार्थों के कारण इस धिनौनी राजनीति को जहॉ हतोत्साहित किया जाना चाहिये था, वही उसे प्रत्यक्ष सा अपरोक्ष रूप से संरक्षण दिया जा रहा है। हिंसा आगजनी ,तोड़ फोड़ धारा 144 कर्फ्यु और इसके बाद गोली चलाने तक की नौबत आ जाती है। फिर हिंसा को लेकर राजनैतिक रोटियॉ सेंकी जाती है।आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी घटनाओं के पीछे जो भी हो उन्हें उनके कृकृत्यों के साथ उजागर किया जाय ताकि जनता असलियत से वाकिफ हो सके। भारत का राजनैतिक

शेष पृष्ठ क्रमांक 4 पर

क्या भारत की राजधानी या स्थान बदल देना चाहिए

हाल ही में दिल्ली में प्रदूषण की चर्चा पूरे भारत सहित दुनिया भर के देशों में होती रही । केवल प्रदूषण ही नही अपितु दिल्ली की भौगोलिक एवं राजनैतिक स्थिति भी अच्छी नही कही जा सकती। प्रश्न उठता है कि भारत की राजधानी को दिल्ली से हटाकर क्यों न मध्य भारत में किसी उपयुक्त स्थान पर बसा दिया जाये। नीचे लिखी समस्याओं के कारण दिल्ली शहर भारत की राजधानी बनने योग्य नही है –

1. जलवायु :– दिल्ली नगरी की जलवायु सम शीतोष्ण नही है। यहाँ की जलवायु अति विषम है अर्थात गर्मी में अतिगर्मी तथा ठंड में प्रति ठंड पड़ती है।

2. धूल/कोहरा :– राजस्थान की धूल भरी आंधी से हमेशा यहॉ का आकाश धूल से आच्छादित रहता है और इस कारण यहॉ कोहरा भी अधिक छाया रहता है।

3. प्रदूषण :– नालों की गंदगी, मार्श, गैसों की अधिकता तथा हवा में सूक्ष्म त्रिसरेणु तथा प्रदूषकों की मौजूदगी के कारण वातावरण उमस भरा, श्वास संबंधी रोगों को बढ़ाने वाला है। ब्रोंकाइटिस अस्थमा से लोग प्रायः प्रभावित रहते हैं।

4. पेयजल :– पेय जल के लिए इस नगर का अपना कोई स्त्रोत नही है। पेय जल प्रदाय के लिए इसे हरियाणा पर निर्भर रहना पड़ता है।

5. असुरक्षा :– सीमा से नजदीक होने के कारण युद्ध के समय दुश्मन की मारक रेंज में आसानी से आता है। आतंकवादियों की पहुंच भी इस कारण यहॉ तक आसान है।

6. भूकंप के लिए अति संवेदनशील जोन –4 पर स्थित :– दिल्ली शहर हमेशा ही भूकंप के झटके प्रतिवर्ष सहता रहता है। रिक्टर स्केल के अनुसार 8 तीव्रता के भूकंप इस शहर में आ सकते है। यह शहर ऐसे बेल्ट में स्थित है कि हमेशा ही इसे भयानक भूकंप का खतरा बना हुआ है। इस संभावना को नकारा नही जा सकता कि यहॉ कभी न कभी 8–9 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। अतः समय रहते हमें जाग जाना चाहिए।

7. वर्षा :– वर्षा अत्यन्त कम होती है किन्तु एक दिन भी बरसात हो जाये तो सड़कों पर पानी भर जाता है और यातायात व्यवस्था ठप्प जाती है। जल निकासी व्यवस्था का अभाव है।

8. बाढ़ :– वैसे यमुना नदी में विनाशकारी बाढ़ नहीं आई। किन्तु इस बात को नकारा नही जा सकता कि कभी यह नगर भीषण बाढ़ में डूब सकता है तथा नुकसान उठा सकता है। इस नगर के बहुत से भाग यमुना की रेत पर, यमुना के निचले तट स्तर पर बसे हुए हैं।

9. जनसंख्या, वाहनों की संख्या तथा यातायात में अवरोध :– यहॉ पर गंतव्य स्थल तक समय पर पहुंचने की कोई गारंटी नहीं। ऑफिस, दुकान, स्टेशन,कार्यालय आदि तक समय पर पहुंचने के लिए बड़ी भारी प्लानिंग करनी पड़ती है न मालूम कहॉ पर ट्राफिक जाम हो जाये। समय पर पहुंचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है।

10. दिल्ली को राज्य घोषित करने में कठिनाई :– अभी दिल्ली केन्द्रशासित क्षेत्र है किन्तु यहॉ पर अन्य प्रदेशों की तरह विघानसभा भी है जो दिल्ली को प्रदेश घोषित करना चाहती है। यहॉ मुख्यमंत्री भी होता है जो संपूर्ण दिल्ली पर शासन करने के लिए पुलिस, सुरक्षा सब कुछ अपने अधीन चाहता हैं। इस कारण केन्द्र और विधानसभा में समन्वय, सामंजस्य का अभाव रहता है और टकराहट बनी रहती है जो बहुत बुरी बात है। ऊपर लिखी समस्याओं को देखकर ऐसा लगता है कि दिल्ली को छोड़कर भारत की राजधानी कहीं अन्यत्र बना लेनी चाहिए। शुभस्य शीघ्रम्

– राजेन्द्र शर्मा

साउथ एशियन हिस्ट्री फॉर ऑल है एक छद्म समूह

दक्षिण एशियाई इतिहास बहुत समृद्ध है। भले ही दशिण एशिया में आज भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मालदीव देश भी आते हैं। इन सभी देशों की अपनी महत्ता है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि भारत और इसकी प्राचीन सभ्यता, सांस्कृतिक धरोहर को जाने – समझे बिना दक्षिण एशिया का इतिहास अधूरा है। कैलिफोर्निया पाठ्यपुस्तक मामले में 'साउथ एशियन हिस्ट्री फॉर ऑल' नामक छद्म समूहों ने कक्षा छह से आठ तक की पाठ्यपुस्तकों में दूसरे मत–पंथों के समान प्राचीन भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक मूल्यों व उसकी रूपरेखा अपनाए जाने के मामले में अंतिम क्षणों तक बाधाएं खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह छद्म समूह इसी एक बात को लेकर पीछे अड़ा रहा कि वंचित, सिख और मुसलमानों के इतिहास को नकारा जा रहा है इस समूह ने भारतीय इतिहास में हिंदुत्व के पूरे के पूरे अध्याय को ही बेकार ठहराने की कोशिश की, लेकिन यह अपनी बात के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया। इस समूह को उस समय मुंह की खानी पड़ी जब हिंदू एजुकेशन काउंसिल की टीम ने अकाट्य तर्क दिया कि हिंदुत्व तो पुस्तक की मूल रूपरेखा का एक अंश है। जहॉ तक वर्ण व्यवस्था में निम्न जाति अथवा वंचित का सवाल आया तो हिंदू एजुकेशन फांउडेशन ने याद दिलाया कि पिछले साल ही सुनवाई के समय रूपरेखा में तथाकथित वंचित वर्ग से आने वाले संतों की मौजूदगी को स्वीकार कर लिया गया था सुनवाई के अंतिम दिन भी इस समूह के दो दर्जन लोगों ने दो बार प्रतिवेदन पढ़ने की कोशिश की, कैलिफोर्निया शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बहस की और पूरे मामले को अदालत में घसीटने की धमकी दी। पता चला है कि इन लोगों में कथित तौर पर कुछ खालिस्तानी, ईसाई मिशनरी के प्रायोजित लोग थे, जो कैलिफोर्निया शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को विषय से भटकाना चाहते थे। सच यह है कि इनमें एक श्वेत अमेरिकी ने विभाग को गुमराह करने की भी कम कोशिश नहीं की। वहीं एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला तो बोर्ड मुख्यालय में सैकड़ों लोगों के बीच जमीन पर ही पसर गई। इसके अलावा भी कुछ लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन वे कोई दबाव बनाने में सफल नहीं हो सके। आठ घंटे तक चली सुनवाई के बाद स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने इस छद्म समूह के किसी बहकावे में आए बिना एजेंडे के अनुरूप रूपरेखा को अंतिम रूप देने में महती भूमिका निभाई और हिंदू एजुकेशन फांउडेशन के करीब 600 प्रतिनिधियों के तर्कसम्मत प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए हिंदू फोबिया से ग्रस्त साउथ एशियन हिस्ट्री फॉर ऑल के सभी तर्कों को नकार दिया।

बंगाल सीमा पर बढ़ता खतरा

कुछ दिन बाद बंग्लादेश में चुनाव होने हैं। ऐसे में यहां का प्रशासन जिहादी गुटों और उसमें शामिल कट्टरपंथी तव्वों को देश से खदेड़ने या पकड़ने के प्रयास में लगा हुआ है। बंग्लादेश की बीजीबी और आरएबी की सक्रियता से ऐसे तत्व वहां से भाग कर पश्चिम बंगाल के मालदा को अपना ठिकाना बना रहे हैं। दरअसल मालदा की सीमा बंगलादेश के चांपाइ नबावगंज जिले से सटी है। कुछ दिन पहले यहीं पर जिहादियों के साथ बीजीबी और आरबी के बीच गोलीबारी हुई थी। मीडिया रपटों की मानें तो इसमें तीन जिहादी मारे गये और बाकी भाग जाने में सफल रहे। ये सभी जमात के लोग थे। खबरों की मानें तो ये भागे हुए जिहादी भारत की सीमा में चले गए हैं। ऐसे में सीमा सुरक्षा बल की ओर से जिन जिलों की सीमा बंग्लादेश से लगी है, उन सभी को रेड एलर्ट जारी किया गया। इस सबके बाद भी पिछले 28 नवंबर की रात को मालदा और मुर्शिदाबाद में कट्टरपंथियों ने सीमा पर लगे कंटीले तारों को काटने की कोशिश की तो सुरक्षाबलों ने उन पर गोलियां बरसाई। हालांकि सीमा सुरक्षा बल ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर रहा है लेकिन सीमावर्ती गांव के लोगों का कहना कि बंग्लादेश के सुरक्षाबलों से बचने के लिए जिहादी गुट भारत में आने के लिए सीमा पर लगी बाड़ काटने की कोशिश में है। ऐसे में सीमा पर तनावपूर्ण माहौल है। यहां एक बात और गौर करने वाली है कि मालदा और बंग्लादेश की सीमा 172 किलोमीटर लम्बी है। इसमें 50 किलोमीटर की सीमा खुली है। इस सीमा में कई नदियों की जल सीमा है। लेकिन मालदा के उन्नयन प्रखंड की सीमा जिहादी और असामाजिक तत्व, पशु तस्करी और जाली मुद्रा की तस्करी के लिए सबसे सरल है, जहां से वे बड़ी आसानी के साथ अपना काम करते हैं। समय–समय पर विभिन्न खुफिया एजेंसी इसको लेकर सचेत करती रहती हैं। इस प्रखंड से बंग्लादेश के तलकुप्पी मानाकासा, अलकूनी गांवों की दूरी केवल आधा किलोमीटर ही है। इन बंग्लादेशी गांवो से ढाका 400 किमी.की दूरी पर है, राजधानी शहर ढाका से दूरी और दुर्गम स्थान पर जमात–ए–इस्लामी सहित विभिन्न जिहादी गुटों ने अपने आधानर शिविर इन्हीं गांवों में बनाए हैं मीडिया रपटों की मानें तो खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस जमात–ए–इस्लामी को भरपूर सहयोग दे रहा है। तो दूसरी ओर जाली मुद्रा का कारोबार भी इनको धन मुहैया कराता है। बंग्लादेश के विभिन्न स्त्रोतों से पता चला है कि पांच जाली मुद्राओं में से तीन मुद्रा आईएसआई द्वारा चलाई जाती हैं सभी जिहादी गुट बंग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। जब इस बात की भनक हसीना सरकार को हुई तब जाकर जिहादी गुटों के खिलाफ अभियान चलाया गया, वह भी अचानक। उल्लेखनीय है कि ऐसे जिहादी तत्वों को भारत के अंदर से भी मदद के प्रयास किए गए, इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सीमाक्षेत्र पर उनके लोग हर तरह से उनकी मदद करते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की मानें तो जिन–जिन गांवों से बंग्लादेश की सीमा सटी है, वहॉ चौकसी के नाम पर खास इंतजाम नहीं है। कभी भी यहां कोई आ–जा सकता है। यहां से तस्कर एवं अन्य असामाजिक गाहे–बगाहे तत्व आते–जाते हैं। हाल ही में कई आतंकी भी पकड़े गए हैं।

पाकिस्तान : हिन्दू तीर्थ कटासराज

पाकिस्तान के जिला चक्रवाल में प्रख्यात हिन्दू तीर्थ कटासराज स्थित है। पाकिस्तानी समाचार पत्रों में इन दिनों इस तीर्थ के बारे में खबरे छप रही हैं। पाक हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट ने कतिपय कड़े आदेश भी जारी किये है। कुछ दिनों पहले खबर थी कि इस मंदिर से भगवान श्रीराम और हनुमान की मूर्तियॉ चोरी हो गयी। कटासराज का पवित्र सरोवर सूख गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तालाब के पास स्थित सीमेंट के कारखाने के कारण, भारी भूजल दोहन के फलस्वरूप यह सरोवर सूखा है। इस मंदिर के आसपास के आवासीय क्षेत्र में इस सीमेंट कारखाने के चलते स्तन केंसर और सॉस सम्बंधी बीमारियॉ फैल गयी हैं चर्चित है कि इस सरोवर में जो स्नान करता था उसकी शारीरिक पीड़ाओं के अलावा सभी पाप घुल जाते थे। बतलाया जाता है कि मंदिर परिसर के सात गृह स्थल हैं जो नौसौ वर्ष पूर्व बनेथे।

26 जनवरी से जुड़े रोचक तथ्य

❁ 1930 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार स्वराज्य दिवस मनाया गया

❁ 1950 में भारत एक संप्रभु लोक तंत्रात्मक गणराज्य घोषित हुआ और इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ। लेकिन दिलचस्प तथ्य यह है कि इंडियन स्टेंडर्ड टाईम के अनुसार दस बजकर अठारह मिनिट पर लागू हुआ था। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी ने गवरमेंट हाऊस के दरबार हाल में पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ लीया। दूरबिन स्टेडियम में झंडा फहराया था।

❁ 26 जनवरी 1965 को हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया।

❁ मयूर के अद्भुत सौन्दर्य के कारण भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घेषित किया।

पृष्ठ क्रं. 1 का शेष भाग

इतिहास गवाह है कि खुद को सत्ता में आने के लिये कॉग्रेस किस हद तक जाकर देश – विरोधियों के साथ हाथ मिलाती रही है। गुजरात चुनाव में खुद को दलित नेता बताने वाले जिग्नेश मेवाणी को इस्लामी आतंकियों से पैसा दिलाकर गुजरात में समाज को बॉटने की कॉग्रेसी चाल का पर्दाफास हो चुका है। इस तथ्य को भी नजर अन्दाज नही किया जाना चाहिये कि प्रत्येक जाति, सम्प्रदाय, धर्म की अपनी गरिमा होती है जिसका सम्मान किया जाना चाहिये। यह सच है कि इस समय देश में राजनैतिक स्वार्थ का दौर चल रहा है जिसके तहत बोट बैक के नजरिये से सारे पहलुओं पर दृष्टि जमायी रखी जाती है। यह अत्यन्त चिन्तनीय दृश्य है। इसके चलते दुराग्रही करते तो हैं धर्मनिरपेक्षता की बातें, पर वे देश को जातिवाद के घोर दलदल में ढ़केले चले जा रहे हैं। यद्यपि यह कहने में संकोच भी नही होना चाहिये कि जातीय समीकरण हमारे देश की राजनीति की एक कड़वी सच्चाई है। सभी दल प्रकारान्तर से अपनी सुविधा के लिये इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन मीडिया को कम से कम इस हवा में नही बहना चाहिये। जातिवाद के दुष्चक्र और चंगुल से मुफ्त होने का यही उपाय है जो पुरातन मंत्र में निहित है '' सब सुखी हों, सब स्वस्थ हों, सर्वत्र सम्यकत्व हो, किसी को दुःख का कोई भाग न मिले। लेकिन अक्सर होता यह है कि राजनीति, समुदायों के बीच वैमनस्य की स्थिति निर्मित कर एक तबके या कई तबकों के समुदाय का समर्थन प्राप्त करने की होड़ करने लग जाती है। महाराष्ट्र (पूना) में बिना बात के जो बबाल हो गया, वह इस बात का पुख्ता सबूत है कि छुद्र राजनीति क्या नही करा सकती ? यह हिंसा की आग गुजरात तक जा पहुँची। ये दोनो राज्य दशकों से कॉग्रेस को सत्ता से दूर रखे हुये हैं। यह जातिवादी मुददा देश को अच्छा संदेश नही दे रहा है। समाज मीडिया से क्या अपेक्षा रखता है ? यही कि वह हमें बताये कि देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, अच्छा क्या है, खराब क्या है।

समृद्धि के सौपान

भारत को निर्माण का वैश्विक केन्द्र बनाने और विनिर्माण के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये लगभग तीन साल पहले 25 सिंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मेक इन इण्डिया का अभियान की शुरूआत की थी। भारत में वैश्विक निवेश और विनिर्माण को आकर्षित करने की यह योजना आगे चलकर एक अंतराष्ट्रीय मार्केटिंग अभियान के रूप में भी सामने आयी। मेक इन इण्डिया अभियान इसलिये शुरू किया गया जिससे भारत में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हो और अर्थव्यवस्था को बढावा मिले।इसका एक आयाम देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देना और घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों की हालात दुरूस्त करना भी है।मेक इन इण्डिया अभियान में सरकार ने ऐसे 25 क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमे हमारे वैश्विक अगुआ बनने की क्षमता है। वर्तमान में देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का योगदान 15 प्रतिशत है। इस अभियान का लक्ष्य एशिया के अन्य विकासशील देशों की तरह इसे 25 प्रतिशत करना हैं। इस प्रक्रिया में सरकार को उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न होगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित होगा और भारत को विनिर्माण केन्द्र में तब्दील किया जा सकेगा। मेक इन इण्डिया का अभियान का 'लोगो' एक शेर है जो अशोक चक्र से प्रेरित है जो भारत की हर क्षेत्र में सफलता को दर्शाता है। इस अभियान को प्रधानमंत्री ने 1916 में जन्में प्रसिद्ध देश भक्त, दार्शनिक और राजनीतिक विभूति पं. दीनदयाल उपाध्याय को समर्पित किया हैं।

मेक इन इण्डिया की कुछ उपलब्धियां

- भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई,यह वृद्धि तब हुई जब वैश्विक एफडीआई दर में गिरावट रही।
- लाइसेंसिंग, सुरक्षा और पर्यावरण मंजूरी जैसी प्रक्रियाओं को सरल बनाने से व्यापार करने की सुगमता (इज ऑफ डूडिंग बिजिनेय) सूचकांक में भारत ने सुधारी अपनी स्थिति।
- रक्षा क्षेत्र तथा इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और निर्माण के क्षेत्र में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि, नतीजतन आयात निर्भरता में आई कमी।
- कपड़ा, फुटवियर और चमड़ा उद्योग को प्रदान की नई ऊर्जा।

मेक इण्डिया के तीन साल– चीन आउट सोर्सिंग, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में भारत का प्रमुख प्रतिद्वंद्वि है। विनिर्माण केन्द्र बनने में भारत का खाराब बुनियादी ढांचा और लचर संचालन व्यवस्था सबसे बड़ी बाधा है। पिछली सरकारों का नौकरशाही नजरिया, सुगम परिवहन की कमी और बड़े पैमाने पर फैला भ्रष्टाचार निर्माताओं के लिये समय पर उत्पाद करना मुश्किल करता था। मोदी सरकार ने इन सब बाधाओं को दूर करने का वादा किया है जिससे निवेशकों के लिये यहां उद्योग स्थापित करना आसान हो। मेक इन इण्डिया का मकसद भारत में औद्योगिक उत्पादन को बढाना है। इस द ृष्टि से प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के मामले में मोदी सरकार का प्रदर्शन मनमोहन सरकार से बेहतर रहा है, 2011–12 में यह आंकड़ा बढकर 149 अरब डॉलर हो गया था।

सूचना

कृपया आप ~~अपना ई~~–मेल एवं मोबाइल नम्बर महाकौशल संदेश के ई मेल पर भेजने का कष्ट करें ताकि 'महाकोशल संदेश' आपको ईमेल पर प्रेषित किया जा सके । – सम्पादक

प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. किशन कछवाहा द्वारा विश्व संवाद केन्द्र, महाकोशल, प्लाट नं–1, म.नं. 1692, नवआदर्श कालोनी, के लिये ओम आफसेट प्रिन्टर्स 239, यूनियन बैंक के सामने बल्देवबाग चौक, जबलपुर द्वारा मुद्रित। प्रकाशन स्थान–विश्व संवाद केन्द्र प्लाट नं 1, म.नं. 1692 नवआदर्श कॉलोनी गढ़ा मार्ग जबलपुर मध्यप्रदेश । संपादक– डॉ. किशन कछवाहा
Email:- vskjbp@gmail.com kishan_kachhwaha@rediffmail.com